Token strike by Officers of Public Sector Undertakings

SHRI DIPEN GHOSH *(West* Bengal) : Madam Deputy Chairman, through you I want to draw the attention of the House to the fact that yesterday the officers of all me public sector undertakings at the Centre had gone on a day's token strike to press for settlement of their demands pending for tne last three years. As a part of their on-going agitation for the last three years, having found no settlement of their demand, they bad organised **a** day's token strike to draw the attention of the Government for immediate settlement of their demands.

Madam, I raise this issue particularly because in he re-cert past we had seen that the officers of the oil sector bad gone on a day's strike and the Government, having failed to setle their issues, tried to thwart the strike by taking recourse to ESMA, which we objected to. The telecom engineers had gone on agination which. resulted into dislocation of telecommunication service. Only yesterday, after the intervention of the Members of Parliament the Government arrived at a sort of settlement end trereafter the telecom engineers withdrew their agitatior. But bofore this one day's strike which was held yesterday works cut into an indefinite strike, bringing all the public sector undertakings to a halt, the Government should immediately take note of this and make serious attempts to arrive at a negotiated settlement with the officers of the public sector undertakings.

The National Confederation of the Public Sector Undertakings officers h-?.d been making certain demands about pay and dearrsess allowances to the public sector employees. There had a Committee of Secretaries. The issues were referred to the court, then again to an expert body and then to the court, but no settlement has yet been arrived at. So, again I would request the Government of India to immediately make serious attempts so that a negotiated settlement is arrived at before the officers of the public sector undertakings went in for a*n* indefinite strike.

Need to exempt certain areas in Rajasihan from the provisions of Forests Conservation Act, 1980

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हम सब यह बात जानते हैं कि आदिवासी, हरिजन और जन-जाति के लोग अधिकतर देश के उन अंचलों में रहते हैं जहां पर जंगल या माइन्स होती हैं । हम लोग इस बात को जानते हैं कि माइन्स का उद्योग, खनिज उद्योग का देश के आर्थिक विकास में बहुत योगदान रहा है । लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि जो फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट बना और जो वायुप्रदूषण का कानून बना या जो दूसरी व्यवस्थायें बनाई गई उनके कारण माइंस उद्योग को सबसे बड़ा आघात लगा है । वहां पर जहां माइन्स पर काम होता है जहां माइन्स स्थित होती हैं वहां पर जंगल अवश्य होते हैं । लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ समय से माइंस का जो काम है वह धीमा पड़ गया है । उसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार की ओर से जो फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट बनाया गया है उसमें कई सारी बाधायें होने के कारण उनको लायसेंस या लीज नहीं मिल पा रही हैं । उसका प्रमुख कारण यह बनता जा रहा है कि गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता । माइन्स तो गांव में रहती है, जंगल में होती हैं, वहां के रहने वालों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ेगा । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां माइन्स स्थित हैं, जैसे राजस्थान में मैंगनासाइट की माइंस हैं, उड़ीसा के अंदर जम-स्टोन की माइंस हैं । ये कुछ ऐसे विशेष खनिज हैं जो कि बहुत कम इस देश में पाये जाते